इकनॉमिक टाइम्स कमोडिटीज़

CM की वॉर्निंग के बावजूद शुगर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहतीं महाराष्ट्र की मिलें

Jan 12, 2016, 09.00 AM IST

[जयश्री भोसले | पुणे]

महाराष्ट्र की शुगर मिलों पर एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दबाव बढ़ने के बावजूद मिलें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहतीं क्योंकि उनके लिए अब डोमेस्टिक मार्केट एक्सपोर्ट से ज्यादा फायदेमंद हो गया है। इसके अलावा सूखा पड़ने से कुछ मिलों के प्रॉडक्शन में भी काफी कमी भी आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने मिलों को चेतावनी दी थी कि अगर वे एक्सपोर्ट नहीं करतीं तो उनसे सरकारी रेट पर पीडीएस के लिए चीनी ली जाएगी।

एक्सपोर्टर्स अभी चीनी के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम की एक्स-मिल कीमत ऑफर कर रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में होलसेल प्राइसेज 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं। केंद्र सरकार ने 2015-16 सीजन में देश में सभी चीनी मिलों के लिए चीनी के एक्सपोर्ट का अनिवार्य कोटा तय किया है। इसे गन्ने की पेमेंट चुकाने के लिए 45 रुपये प्रति टन की सब्सिडी लेने से जोड़ा गया है।

फड़नवीस ने पिछले सप्ताह शुगर इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम के दौरान मिलों को चेतावनी देते हुए कहा था, 'अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो हमें पीडीएस के लिए रेगुलेटेड प्राइस पर मिलों से चीनी लेने के बारे में सोचना पड़ सकता है।' शुगर इंडस्ट्री ने सरकार के साथ संबंध बेहतर करने के लिए काफी कोशिश की है, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेज में बढ़ोतरी की वजह से इंडस्ट्री में अब इस बात को लेकर विभाजित है कि पहले एक्सपोर्ट कौन करेगा। महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री से जुड़े एक सीनियर एग्जिक्यूटिव ने बताया, 'प्राइवेट मिलें चाहती हैं कि कोऑपरेटिव मिलें पहले एक्सपोर्ट करें। कोटा पूरा करने के लिए अभी सितंबर तक का समय बचा है और ऐसे में मिलें अभी डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेज का फायदा उठाने में दिलचस्पी ले रही हैं।'

इंडस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि अभी तक भारतीय एक्सपोर्टर्स ने लगभग नौ लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट के लिए डील की हैं और इसमें से करीब 4.5 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया जा चुका है। सूखा प्रभावित इलाकों में मौजूद चीनी मिलों ने सरकार से एक्सपोर्ट कोटा में उन्हें छूट देने की मांग की है।

वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन (WISA) के प्रेसिडेंट बी बी थांब्रे ने बताया, 'हमने केंद्र सरकार से मराठवाड़ा क्षेत्र और सोलापुर और अहमदनगर जिलों में मौजूद चीनी मिलों के लिए एक्सपोर्ट कोटा तय करने के तरीके में बदलाव करने के लिए बात करने का फैसला किया है। इसे पिछले तीन वर्षों के एवरेज प्रॉडक्शन के 12 पर्सेंट पर रखने के बजाय मौजूदा वर्ष में प्रॉडक्शन पर आधारित किया जाना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि उनकी अपनी मिलों की गन्ने की पेराई की क्षमता पिछले वर्ष 6.5 लाख टन से घटकर इस वर्ष 2.5 लाख टन रह गई है। इसे देखते हुए सूखा प्रभावित इलाकों में मौजूद कुछ मिलों के लिए तय की गई एक्सपोर्ट की मात्रा उनके मौजूदा प्रॉडक्शन की 40-50 पर्सेंट हो जाएगी।